गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 044
दि. 13.06.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

युवा सपनों को ऊंची उड़ान

गुजरात सरकार

2.2 लाख स्टार्टअप्स से युवाओं को रोजगार और नवाचार के अवसर

10,000+ अटल टिंकरिंग लैब्स से **1.1+ करोड़** छात्र विज्ञान और तकनीक से जुड़े

12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के

2 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और देश में 2.2 लाख स्टार्टअप्स के जरिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने युवा सपनों को नई उड़ान दी है। - **श्री हर्ष संघवी,** माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात

शांति की घोषणा या रणनीतिक दांव? ट्रंप के दावे और ईरान के खंडन ने बढ़ाया वैश्विक सस्पेंस

वाशिंगटन। मध्य पूर्व में महीनों से जारी तनाव, सैन्य टकराव और कूटनीतिक खींचतान के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष समाप्ति की ओर बढ़ चुका है और दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर सहमति बन गई है। लेकिन इस दावे के कुछ ही घंटों बाद ईरान की ओर से आए आधिकारिक खंडन ने पूरे घटनाक्रम को रहस्य और अनिश्चितता के घेरे में ला खड़ा किया है। अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में शांति की दिशा में कोई निर्णायक प्रगति हुई है या फिर यह कूटनीतिक दबाव और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भर है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने जॉर्जिया में आयोजित एक वर्चुअल चुनावी रैली के दौरान अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को रोक दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने भविष्य में परमाणु हथियार विकसित न करने की शर्त को स्वीकार कर लिया है और दोनों पक्षों के बीच व्यापक सहमति बन चुकी है। ट्रंप के अनुसार यह बातचीत ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंची और वहां से मंजूरी भी मिल चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि इसी कारण उन्होंने ईरान के खिलाफ प्रस्तावित सैन्य हमलों को अंतिम समय में रद्द करने का निर्णय लिया।

ट्रंप के इस बयान ने दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञों और राजनयिकों को चौंका दिया। क्योंकि जिस संघर्ष को लेकर पिछले कई महीनों से तनाव बना हुआ था, उसके अचानक समाप्त होने की घोषणा ने अनेक नए सवाल पैदा कर दिए। खास बात यह रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने केवल युद्धविराम की बात नहीं कही, बल्कि एक व्यापक क्षेत्रीय समझौते का भी संकेत दिया। उनके अनुसार इस प्रस्तावित समझौते को इजरायल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और मिस्र सहित कई देशों का समर्थन प्राप्त है।

हालांकि ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तब तक क्षेत्र में लागू नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी। इससे यह संकेत मिला कि बातचीत अंतिम चरण में होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर के समय और स्थान की घोषणा जल्द की जाएगी।

लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे के तुरंत बाद ईरान ने पूरी तस्वीर बदल दी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी समझौते को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने ट्रंप के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि समझौते को ईरानी नेतृत्व की मंजूरी मिल चुकी है। बघाई ने कहा कि ईरान में विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निर्णय निर्धारित संस्थागत प्रक्रिया के तहत लिए जाते हैं और अभी तक ऐसी किसी मंजूरी की घोषणा नहीं की गई है।

ईरान के इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। यदि वास्तव में समझौता अंतिम चरण में है तो फिर ईरान सार्वजनिक रूप से उसका खंडन क्यों कर रहा है? और यदि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है तो अमेरिकी राष्ट्रपति इतने आत्मविश्वास के साथ उसकी घोषणा क्यों कर रहे हैं? यही प्रश्न इस समय वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है।

इस घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू इजरायल की प्रतिक्रिया है। कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप की घोषणा से पूरी तरह आश्चर्यचकित रह गए। बताया जा रहा है कि उन्हें इस संभावित समझौते की पूर्व जानकारी नहीं थी। यदि यह सच है तो यह अमेरिका-इजरायल संबंधों में एक असामान्य स्थिति मानी जाएगी, क्योंकि मध्य पूर्व से जुड़े बड़े रणनीतिक फैसलों में दोनों देशों के बीच घनिष्ठ समन्वय देखा जाता रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच कोई व्यापक समझौता होता है तो उसका सीधा प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। विशेष रूप से लेबनान, सीरिया, इराक और खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ऐसी किसी डील के तहत इजरायल को भी अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है, हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

ट्रंप ने अपने बयान में एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ईरान पर होने वाले एक बड़े सैन्य हमले को शुरू होने से केवल तीन घंटे पहले रोक दिया था। इससे पहले वे ईरान के रणनीतिक महत्व वाले खार्ग द्वीप को लेकर कड़ी चेतावनियां दे चुके थे। ऐसे में उनका अचानक नरम रुख अपनाना कई पर्यवेक्षकों को राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लग रहा है।

इस पूरे विवाद के बीच ट्रंप की विश्वसनीयता भी चर्चा का विषय बनी हुई है। आलोचकों का कहना है कि वे अतीत में भी कई बार ईरान के साथ वार्ता, समझौते और युद्ध समाप्ति को लेकर बड़े दावे कर चुके हैं। राजनीतिक विरोधियों का आरोप है कि इससे पहले भी कई अवसरों पर उन्होंने ऐसी घोषणाएं कीं जो बाद में वास्तविकता में परिवर्तित नहीं हुईं। यही कारण है कि इस बार भी उनके दावों को लेकर व्यापक संदेह बना हुआ है।

दूसरी ओर अमेरिकी प्रशासन संभावित समझौते की तैयारियों में सक्रिय दिखाई दे रहा है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी सैन्य और कूटनीतिक तंत्र को अलर्ट पर रखा गया है। यूरोप में अमेरिकी गतिविधियों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। चर्चा है कि यदि समझौता अंतिम रूप लेता है तो अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। जिनेवा को संभावित वार्ता स्थल के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

इस बीच क्षेत्र से कई अन्य दावे भी सामने आ रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि हालिया संघर्ष के दौरान अमेरिकी सैन्य संसाधनों को नुकसान पहुंचा है, जबकि ईरान समर्थक सूत्रों ने बहरीन में अमेरिकी लॉन्ग-रेंज रडार सिस्टम पर हमले का दावा किया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और न ही अमेरिका या बहरीन की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी किया गया है।

वैश्विक बाजार भी इस घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए हैं। तेल की कीमतों से लेकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा तक, इस संघर्ष का प्रभाव कई स्तरों पर महसूस किया जा रहा है। यदि वास्तव में कोई स्थायी समझौता होता है तो यह मध्य पूर्व में वर्षों से चले आ रहे तनाव को कम करने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। वहीं यदि यह केवल राजनीतिक बयानबाजी या दबाव की रणनीति साबित होती है, तो क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ सकती है।

फिलहाल स्थिति ऐसी है जहां दावों और खंडनों के बीच सच्चाई कहीं छिपी हुई प्रतीत होती है। एक तरफ ट्रंप शांति और समझौते की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर ईरान किसी अंतिम सहमति से इनकार कर रहा है। दुनिया की निगाहें अब आने वाले दिनों पर टिकी हैं। यही दिन तय करेंगे कि यह घोषणा इतिहास बदलने वाली शांति पहल साबित होगी या फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक और अधूरा अध्याय बनकर रह जाएगी।

आसमान का प्रहरी बनेगा 'नेत्रा': दुश्मन की हर गतिविधि पर रहेगी भारत की पैनी नजर

नई दिल्ली। बदलते युद्ध स्वरूप, आधुनिक तकनीक और बढ़ते सुरक्षा खतरों के दौर में किसी भी देश की सैन्य शक्ति केवल उसके लड़ाकू विमानों, मिसाइलों या सैनिकों की संख्या से नहीं आंकी जाती, बल्कि इस बात से तय होती है कि वह दुश्मन की गतिविधियों का कितनी जल्दी और कितनी सटीकता से पता लगा सकता है। आधुनिक युद्धों में सूचना ही सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत ने स्वदेशी तकनीक के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित 'नेत्रा' हवाई चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली अब पूर्ण संचालन क्षमता हासिल करने की दिशा में अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। 25 जून को इसे अंतिम संचालन मंजूरी मिलने की संभावना है, जिसके बाद यह भारतीय वायुसेना की रणनीतिक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 'नेत्रा' केवल एक विमान आधारित निगरानी प्रणाली नहीं है, बल्कि यह भारत की हवाई सुरक्षा व्यवस्था की आंख और कान के रूप में कार्य करेगी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह दुश्मन की गतिविधियों को बहुत दूर से पहचान सकती है और समय रहते आवश्यक चेतावनी उपलब्ध करा सकती है। आधुनिक युद्ध में कुछ सेकंड का समय भी निर्णायक साबित हो सकता है। ऐसे में 'नेत्रा' जैसी प्रणाली सेना को पहले से सतर्क रहने और तत्काल जवाबी कार्रवाई की क्षमता प्रदान करती है।

डीआरडीओ के बेंगलुरु स्थित हवाई प्रणाली केंद्र में 25 जून को आयोजित होने वाला कार्यक्रम इस परियोजना के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस दौरान प्रणाली को फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी अंतिम संचालन मंजूरी प्रदान की जाएगी। रक्षा क्षेत्र में एफओसी किसी भी सैन्य प्रणाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। इसका अर्थ है कि प्रणाली ने सभी तकनीकी, परिचालन और सुरक्षा मानकों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है तथा अब उसे वास्तविक सैन्य अभियानों में पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।

'नेत्रा' परियोजना की शुरुआत भारतीय वायुसेना की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए की गई थी। लंबे समय तक भारत को ऐसी प्रणालियों के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि समय के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण पर बढ़ते जोर ने देश को अपनी अत्याधुनिक निगरानी और चेतावनी प्रणालियां विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ाया। इसी सोच का परिणाम 'नेत्रा' है, जिसने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है जो स्वयं ऐसी जटिल तकनीक विकसित करने की क्षमता रखते हैं।

हवाई चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली, जिसे एईडब्ल्यूएंडसी कहा जाता है, आधुनिक वायु अभियानों की रीढ़ मानी जाती है। यह प्रणाली किसी साधारण विमान की तरह केवल उड़ान नहीं भरती, बल्कि आसमान में उड़ता हुआ एक कमांड सेंटर बन जाती है। इसके भीतर अत्याधुनिक रडार, सेंसर, संचार प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरण लगे होते हैं। ये उपकरण सैकड़ों किलोमीटर दूर तक हवाई और समुद्री गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं। यदि कोई लड़ाकू विमान, मिसाइल, ड्रोन या अन्य सैन्य प्लेटफॉर्म भारतीय सीमा की ओर बढ़ता है तो 'नेत्रा' उसे बहुत पहले पहचान सकती है।

इस प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत इसकी व्यापक निगरानी क्षमता है। यह केवल हवाई खतरों तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्र की सतह पर मौजूद लक्ष्यों और गतिविधियों पर भी नजर रख सकती है। इसके कारण भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों को सामरिक लाभ मिलता है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत कमांड सेंटर और ऑपरेशनल इकाइयों तक पहुंचाई जा सकती है, जिससे त्वरित निर्णय लेना संभव हो जाता है।

'नेत्रा' के विकास के लिए एम्ब्रेयर ईएमबी-145 विमान को आधार प्लेटफॉर्म के रूप में चुना गया। इस विमान में विशेष मिशन उपकरण, रडार प्रणाली और संचार नेटवर्क को एकीकृत किया गया। इसके बाद इसे पूर्ण रूप से हवाई चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली में परिवर्तित किया गया। इस परियोजना के तहत तैयार किए गए तीनों विमानों में मिशन प्रणालियों की स्थापना पूरी की जा चुकी है और इन्हें विभिन्न चरणों के परीक्षणों से भी सफलतापूर्वक गुजारा गया है।

इन परीक्षणों में भारतीय वायुसेना ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। उड़ान परीक्षणों, निगरानी अभियानों, डेटा संचार, लक्ष्य पहचान और कमांड नियंत्रण से जुड़े अनेक पहलुओं की जांच की गई। परीक्षणों के दौरान प्रणाली ने अपेक्षित प्रदर्शन किया, जिसके बाद इसे प्रारंभिक संचालन मंजूरी प्रदान की गई थी। अब अंतिम मंजूरी मिलने के बाद यह पूरी तरह युद्धक उपयोग के लिए तैयार मानी जाएगी।

भारतीय वायुसेना पहले से ही इजरायली तकनीक आधारित फाल्कन हवाई चेतावनी प्रणाली का संचालन करती है। यह प्रणाली रूस निर्मित आईएल-76 विमान पर स्थापित है और लंबी दूरी तक निगरानी करने में सक्षम है। फाल्कन प्रणाली ने भारतीय वायुसेना को महत्वपूर्ण सामरिक लाभ प्रदान किया है, लेकिन 'नेत्रा' के आने से देश की स्वदेशी क्षमता और मजबूत होगी। इसके साथ भारत विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता कम करते हुए अपनी जरूरतों के अनुसार तकनीक विकसित कर सकेगा। फाल्कन और नेत्रा दोनों प्रणालियां मिलकर भारतीय वायुसेना की निगरानी क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगी। आधुनिक युद्ध में इन्हें 'फोर्स मल्टीप्लायर' कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि ये प्रणालियां केवल जानकारी नहीं देतीं, बल्कि पूरे सैन्य अभियान की प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा देती हैं। एक लड़ाकू विमान अकेले जितना काम कर सकता है, उतना ही कार्य वह ऐसी निगरानी प्रणाली के सहयोग से कहीं अधिक दक्षता और सटीकता के साथ कर सकता है।

असम-नगालैंड के बीच दशकों का विवाद खत्म, तेल समझौता संपन्न, शाह ने पूर्वोत्तर का भाग्य ही बदल दिया

"हम आपको बता दें कि केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारत सरकार, असम सरकार और नगालैंड सरकार के बीच असम-नगालैंड सीमावर्ती क्षेत्रों में खनिज तेल संचालन (Mineral Oil Operations) के संबंध में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही मोदी सरकार को पूर्वोत्तर से एक बड़ी रणनीतिक सफलता मिली है। केंद्र, असम और नगालैंड के बीच तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण को लेकर हुआ त्रिपक्षीय समझौता भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के अभियान का निर्णायक अध्याय है। दशकों से विवाद और अस्थिरता में फंसे असम, नगालैंड सीमा क्षेत्र में तेल खोज का रास्ता खोलकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मिशन को नई ताकत दे दी है, जिसका लक्ष्य विदेशी तेल निर्भरता घटाकर भारत को ऊर्जा महाशक्ति बनाना है। यही वजह है कि अमित शाह ने इसे विकसित पूर्वोत्तर और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।हम आपको बता दें कि केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारत सरकार, असम सरकार और नगालैंड सरकार के बीच असम-नगालैंड सीमावर्ती क्षेत्रों में खनिज तेल संचालन के संबंध में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा और नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो सहित केंद्र, असम एवं नगालैंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए साफ कहा कि इस समझौते ने विकसित पूर्वोत्तर के रास्ते में खड़ी

अंतिम बड़ी बाधा हटा दी है।

हम आपको बता दें कि असम और नगालैंड की सीमा से लगे विवादित क्षेत्र में तीन दशक से अधिक समय से तेल और खनिज अन्वेषण ठप पड़ा था। अधिकार क्षेत्र को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनाव बना रहता था, जिसके कारण हजारों करोड़ रुपये की संपदा जमीन के नीचे दबी रह गई। अब इस समझौते के तहत एक हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में तेल, गैस और खनिज संसाधनों की खोज और उत्पादन का रास्ता खुल गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों राज्यों ने संसाधनों के बंटवारे पर 50-50 की सहमति बनाई है। यही वह राजनीतिक परिपक्वता है जिसने इस समझौते को टकराव से निकालकर साझेदारी के मॉडल में बदल दिया।

अमित शाह ने दावा किया कि इस एक समझौते से प्रतिदिन एक हजार से पंद्रह सौ बैरल तेल उत्पादन क्षमता को दस गुना तक बढ़ाया जा सकता है। केवल एक तेल क्षेत्र से पंद्रह हजार करोड़ रुपये से अधिक की संभावित प्राप्ति का अनुमान जताया गया है। यह बयान केवल आर्थिक संभावना का संकेत नहीं, बल्कि उस रणनीतिक दिशा का संकेत है जिसमें भारत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, पश्चिम एशिया में अस्थिरता और ऊर्जा आपूर्ति संकटों के दौर में भारत लंबे समय से आयातित तेल पर निर्भरता घटाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में पूर्वोत्तर के विशाल तेल और गैस भंडार भारत के लिए नई ऊर्जा रीढ़ साबित हो सकते हैं। दरअसल यह समझौता केवल तेल निकालने का मसला नहीं है। यह पूर्वोत्तर को संघर्ष की पहचान से निकालकर सामरिक और आर्थिक शक्ति केंद्र में बदलने की कवायद है। अमित शाह ने कहा कि यदि नगालैंड में फैले तेल और गैस भंडार का पूरा दोहन हुआ तो भारत विदेशी देशों पर अपनी ऊर्जा निर्भरता काफी हद तक कम कर सकेगा। इसका सीधा मतलब है कि भारत अपने ऊर्जा हितों को लेकर अधिक स्वतंत्र रणनीति अपना सकेगा। देखा जाये तो ऊर्जा आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक मुद्दा नहीं होती, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मूल तत्व बन चुकी है।

साथ ही इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा बड़ा पहलू सुरक्षा और शांति से जुड़ा है। अमित शाह ने पूर्वोत्तर में हिंसा की घटनाओं में लगभग अस्सी प्रतिशत गिरावट का दावा करते हुए कहा कि वर्ष 2019 के बाद 12 शांति समझौते हुए हैं। यही कारण है कि अब सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को भी पूर्वोत्तर के अधिकांश हिस्सों से हटाने की तैयारी चल रही है। अमित शाह ने विश्वास जताया कि अगले वर्ष एक या दो राज्यों को छोड़कर पूरे पूर्वोत्तर से यह कानून हटाया जा सकता है। यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दशकों तक पूर्वोत्तर की पहचान उग्रवाद, सैन्य उपस्थिति और अस्थिरता से जुड़ी रही है। अब केंद्र सरकार यह संदेश देना चाहती है कि क्षेत्र संघर्ष से विकास की ओर बढ़ चुका है।

रणनीतिक दृष्टि से देखें तो यह समझौता चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ी भारत की व्यापक नीति से भी मेल खाता है। पूर्वोत्तर भारत लंबे समय तक केवल भौगोलिक सीमा माना जाता रहा, लेकिन अब उसे आर्थिक गलियारे, ऊर्जा केंद्र और संपर्क सेतु के रूप में विकसित किया जा रहा है। सड़क, रेल, निवेश, पर्यटन और ऊर्जा परियोजनाओं के जरिए केंद्र सरकार इस क्षेत्र को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रही है। तेल और गैस परियोजनाओं के सक्रिय होने से निजी निवेश बढ़ेगा, रोजगार पैदा होंगे और क्षेत्रीय असंतोष कम होगा। यही वह बिंदु है जहां विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने भी कहा कि यह समझौता देश की दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। वहीं नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की सहमति इस बात का संकेत है कि अब पूर्वोत्तर की राजनीति टकराव से अधिक आर्थिक साझेदारी की दिशा में बढ़ रही है। यही कारण है कि अमित शाह ने इसे जीत हार का नहीं, बल्कि सबकी जीत का समझौता बताया।

बहरहाल, अब स्पष्ट है कि यह त्रिपक्षीय समझौता केवल सीमाई विवाद सुलझाने का प्रयास नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर के भविष्य को नए सिरे से परिभाषित करने की शुरुआत है। यदि सरकार अपने दावों के अनुरूप तेल उत्पादन, निवेश और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सफल रहती है, तो आने वाले वर्षों में पूर्वोत्तर भारत की ऊर्जा शक्ति, सामरिक मजबूती और आर्थिक विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।

संपादकीय

महिलाओं के खिलाफ हिंसा

यूं तो भारतीय समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने के तमाम दावे गाहे-बगाहे किए ही जाते हैं। आधी दुनिया को पूरा हक देने की बात होती है। किंतु-परंतु के बीच उन्हें जनप्रतिनिधि संस्थाओं में 33 फीसदी आरक्षण देने पर प्रतिबद्धता जतायी जाती है। लेकिन इन दावों के बीच सामने आया एक कड़वा सच हमें वास्तविक स्थिति से रूबरू करा देता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि देश में ग्रामीण इलाकों में हर चौथी और शहरी क्षेत्र में हर छठी महिला किसी न किसी रूप में हिंसा का शिकार होती रही है। यह विडंबना ही है कि शहरों की तुलना में ज्यादा शांत व सुरक्षित माने जाने वाले ग्रामीण इलाकों में स्त्रियों को घरेलू एवं यौन हिंसा का ज्यादा सामना करना पड़ता है। वीरवार को सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों के योगदान को राष्ट्र के उत्थान में महत्वपूर्ण बताते हुए उन्हें नेशन बिल्डर तक कह दिया। यहां तक कि घर और परिवार की देखभाल में गृहिणियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के कल्पित आर्थिक मूल्य का निर्धारण करते हुए उसे नजरअंदाज न करने की सलाह दी। यह विडंबना ही है कि जिन महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट नेशन बिल्डर बता रहा है, उन्हें हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आखिर महिला सशक्तीकरण के सारे विशेष प्रयास सिर्फ कागजों तक ही क्यों सिमट जाते हैं? आखिर क्या वजह है कि महिलाओं की रक्षा-सुरक्षा हेतु तमाम विशेष कानून बनाये जाने के बावजूद जमीनी हकीकत नहीं बदलती है। इसमें दो राय नहीं कि समय-समय पर महिला उत्थान के लिये तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं और अभियान चलाये जाते रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विकासात्मक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। जीवन के हर क्षेत्र में वे अपना आकाश तलाश रही हैं। विधायिका में तैंतीस प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल सहमत नजर आते हैं। सवाल यही है कि जीवन व्यवहार में स्थिति क्यों नहीं बदलती। देश के नीति-नियंताओं को इस गंभीर मुद्दे पर विचार करना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिये तमाम विशेष कानून बनाये जाने के बावजूद क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में हर चौथी व शहरी क्षेत्र में हर छठी स्त्री को हिंसा व यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। आखिर क्या वजह है कि घर से लेकर बाहर तक वे खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही हैं? क्या कहीं इसमें पितृसत्ता प्रधान समाज की मानसिकता कारण है? दरअसल, आज लड़कियों व महिलाओं के खिलाफ हिंसा कई रूपों में मौजूद है। आजादी के सात दशक बाद भी हम दहेज के कलंक से मुक्त नहीं हो पाये हैं। हाल के दिनों में दहेज हत्या के कई बहुचर्चित मामले प्रकाश में आए। एक लड़की की पढ़ाई से लेकर शादी तक मां-बाप काफी खर्च करते हैं, फिर दहेज देने की जरूरत क्यों? छोटी-छोटी बातों में महिलाओं से मारपीट की खबरें आती हैं। वहीं अदिवासी व पिछड़े इलाकों में महिलाओं को डायन बताकर मारने की घटनाएं सामने आती हैं। हमारा समाज आज भी अंधविश्वासों और जादू-टोने के भय से मुक्त नहीं हुआ है। जिसके चलते महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले सामने आते हैं। सर्वेक्षण का यह तथ्य चौंकाता है कि 18 से 49 आयु वर्ग की विवाहिताओं में बाईस फीसदी को वैवाहिक जीवन में घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा है। हालांकि, समय के साथ हिंसा के आंकड़ों में गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति चिंता पैदा करती है। जो किसी सभ्य समाज के माथे पर एक दाग की तरह ही है। हमारी व्यवस्था की विसंगतियां, पुरुष प्रधान सोच और हिंसा रोकने के लिये बनाए गए कानूनों के क्रियान्वयन में खामियां महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने में बाधक हैं। जो सामाजिक विसंगति की ओर इशारा करता है। यदि समय रहते कानून प्रवर्तन एजेंसियां संवेदनशील ढंग से कदम उठायें तो महिलाएं खुद को घर-बाहर सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर अवस्था के दौरान यौन-हिंसा का शिकार होने का प्रतिशत शहरों के मुकाबले अधिक होना, ग्रामीण समाज में विद्रूपताओं को दर्शाता है। जरूरी है कि ग्रामीण समाज में महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग किया जाए।

प्रेरणा

जीवन का सच्चा विजयपथ

मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह परिस्थितियों का दास होकर भी उनसे ऊपर उठने की क्षमता रखता है। संसार में ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने अभाव, बीमारी, संघर्ष और विपत्तियों के बीच अपने जीवन का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि वे केवल अपने समय के नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बन गए। प्रसिद्ध चिंतक और साहित्यकार आल्बेयर कामू का जीवन भी इसी सत्य का सशक्त प्रमाण है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयाँ किसी व्यक्ति की शक्ति को समाप्त नहीं करतीं, बल्कि उसके भीतर छिपी हुई वास्तविक क्षमता को सामने लाती हैं।

आल्बेयर कामू का जन्म अल्जीरिया के एक अत्यंत साधारण और गरीब परिवार में हुआ था। बचपन आर्थिक अभावों के बीच बीता। उनके परिवार के पास न तो पर्याप्त संसाधन थे और न ही सुविधाओं से भरा जीवन। फिर भी उनके भीतर सपने देखने का साहस था। वे फुटबॉल खेलना पसंद करते थे और भविष्य में अध्यापक बनने की इच्छा रखते थे। खेल के मैदान में उन्हें आनंद मिलता था और जीवन के प्रति उत्साह भी। वे उन लाखों युवाओं की तरह थे जो अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ते हैं और बेहतर भविष्य की आशा करते हैं।

किन्तु जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। एक दिन बीमारी ने उनके जीवन में दस्तक दी। उनके फेफड़ों में गंभीर रोग हो गया। चिकित्सकों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब उन्हें बहुत सावधानी से जीवन जीना होगा क्योंकि यह बीमारी जीवन भर उनका साथ नहीं छोड़ेगी। एक युवा व्यक्ति के लिए यह समाचार किसी आघात से कम नहीं था। जिस उम्र में लोग भविष्य के सपने बुनते हैं, उस उम्र में उन्हें अपनी सीमाओं का सामना करना पड़ा।

ऐसी परिस्थितियों में अधिकांश लोग निराश हो जाते हैं। वे अपने भाग्य को दोष देते हैं और जीवन से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन कामू ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने बीमारी को अपनी हार का कारण नहीं बनाया। जब उनके एक मित्र ने पूछा कि अब क्या करोगे, तब उन्होंने जो उत्तर दिया, वह उनकी सोच की गहराई को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यदि जीवन सीमित है तो उसे और अधिक गहराई से जीना चाहिए। यह केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण था। उन्होंने समझ लिया था कि जीवन की लंबाई से अधिक महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है।

समय बीतता गया। यूरोप युद्ध, हिंसा और निराशा के दौर से गुजरने लगा। चारों ओर भय, असुरक्षा और अनिश्चितता का वातावरण था। लोग भविष्य को लेकर चिंतित थे। ऐसे समय में भी कामू ने मनुष्य की आंतरिक शक्ति पर विश्वास बनाए रखा। उन्होंने कहा कि मनुष्य की महानता इस बात में नहीं है कि संसार उसे क्या देता है, बल्कि इस बात में है कि वह विपत्ति के सामने कैसे खड़ा रहता है। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था।

वास्तव में जीवन का मूल्य इस बात से नहीं तय होता कि हमारे पास कितनी सुविधाएँ हैं। अनेक लोग संसाधनों से भरपूर जीवन जीते हैं, फिर भी भीतर से असंतुष्ट रहते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। अंतर केवल दृष्टिकोण का होता है। जो व्यक्ति हर कठिनाई को अवसर की तरह देखता है, वह परिस्थितियों से हारता नहीं है। वह उन्हें अपने विकास का साधन बना लेता है। कामू की बीमारी ने उनके शरीर को कमजोर अवश्य किया, लेकिन उनके विचारों को और अधिक मजबूत बना दिया। उन्होंने लेखन को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। उनके अनुभव, संघर्ष और चिंतन उनकी रचनाओं में दिखाई देने लगे। उन्होंने यह दिखाया कि बाहरी सीमाएँ मनुष्य की आंतरिक स्वतंत्रता को नहीं रोक सकतीं। जब मनुष्य के भीतर साहस, विश्वास और उद्देश्य होता है, तब वह किसी भी कठिन परिस्थिति में अर्थ खोज सकता है। आज के समय में भी बहुत से लोग छोटी-छोटी समस्याओं से निराश हो जाते हैं। परीक्षा में असफलता, आर्थिक कठिनाई, नौकरी की चिंता या सामाजिक चुनौतियाँ उन्हें हतोत्साहित कर देती हैं। वे सोचने लगते हैं कि उनका जीवन दूसरों की तुलना में अधिक कठिन है। लेकिन यदि हम इतिहास और महान व्यक्तियों के जीवन को देखें, तो पाएंगे कि सफलता का मार्ग कभी भी आसान नहीं रहा। हर उपलब्धि के पीछे संघर्ष, धैर्य और निरंतर प्रयास की कहानी छिपी होती है।

जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति चुनौतियों से मुक्त नहीं है। हर किसी के हिस्से में कोई न कोई संघर्ष अवश्य आता है। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग उन संघर्षों के सामने झुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें अपने व्यक्तित्व को निखारने का अवसर बना लेते हैं। साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं है, बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ते रहने की क्षमता है। यही क्षमता साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाती है।

जब हम अपने जीवन को गहराई से देखते हैं, तब समझ में आता है कि कठिनाइयाँ वास्तव में हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। वे हमें धैर्य सिखाती हैं, हमारी सीमाओं का परिचय कराती हैं और हमारी छिपी हुई शक्तियों को जगाती हैं। यदि जीवन में केवल सुख ही सुख हो, तो शायद हम अपने वास्तविक सामर्थ्य को कभी पहचान ही न सकें। विपत्तियाँ ही हमें अपने भीतर झांकने और स्वयं को समझने का अवसर देती हैं। आल्बेयर कामू का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, मनुष्य के पास हमेशा एक विकल्प रहता है—हार मान लेने का या साहस के साथ आगे बढ़ने का। जो व्यक्ति दूसरा विकल्प चुनता है, वही अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना पाता है। जीवन की वास्तविक विजय बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस शक्ति में है जो हमें हर कठिनाई के बाद फिर से खड़ा होने का साहस देती है। यही साहस मनुष्य को महान बनाता है और यही वह प्रकाश है जो अंधकारमय परिस्थितियों में भी आगे का मार्ग दिखाता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए, उसे अभिशाप न समझें। उसे अपने व्यक्तित्व को गढ़ने वाला अवसर मानें, क्योंकि अक्सर सबसे उज्ज्वल प्रकाश सबसे गहरे अंधकार के बाद ही दिखाई देता है।

भारत में तो कई बार देखी होगी, अब अमेरिकी सांसदों की भिड़ंत देखिये

भारत में आपने कई बार नेताओं और नेत्रियों के बीच तीखी बहस, जुबानी जंग और राजनीतिक कटाक्ष देखे होंगे, लेकिन इस बार अमेरिका से जो मामला सामने आया है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिकी राजनीति में दो महिला सांसदों के बीच छिड़ी इस भीषण टकराहट ने वहां के लोकतंत्र, प्रवासी राजनीति और राष्ट्रवाद की बहस को नए सिरे से हवा दे दी है। खास बात यह रही कि इस पूरे विवाद में सोमालिया में जन्मीं सांसद इल्हान उमर को करारा जवाब मिला और मामला केवल व्यक्तिगत कटाक्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिकी संसद में विदेशी मूल के नेताओं की भूमिका तक पहुंच गया। दरअसल अमेरिका की रिपब्लिकन सांसद नैन्सी मेस ने एक ऐसा संवैधानिक संशोधन प्रस्तावित कर दिया है जिसने वहां की राजनीति में भूचाल ला दिया है। नैन्सी मेस का कहना है कि जिस तरह अमेरिका का राष्ट्रपति केवल जन्म से अमेरिकी नागरिक ही बन सकता है, उसी तरह संसद के सदस्य, संघीय न्यायपालिका और सीनेट से मंजूर होने वाले महत्वपूर्ण पदों पर भी केवल जन्मजात अमेरिकी नागरिकों को ही बैठने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि विदेशी मूल के लोग अमेरिकी राजनीति में रहकर दूसरे देशों के प्रति निष्ठा रखते हैं और इससे अमेरिका के हित प्रभावित होते हैं।

नैन्सी मेस ने सीधे तौर पर इल्हान उमर, श्री थानेदार और प्रमिला जयपाल जैसे नेताओं का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि इन नेताओं की वफादारी अमेरिका से ज्यादा दूसरे देशों के प्रति दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से अमेरिका ने विदेशी मूल के लोगों को सत्ता के महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचने दिया और अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। नैन्सी मेस ने यहां तक कह दिया कि अगर यह संवैधानिक संशोधन लागू होता है तो वह इसे पुराने मामलों पर भी लागू करने के पक्ष में हैं, यानी पहले से संसद में मौजूद विदेशी मूल के नेताओं की सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है।

इस बयान के बाद अमेरिकी राजनीति में जबरदस्त हंगामा मच गया। इल्हान उमर ने शुरुआत में इस प्रस्ताव को हल्के अंदाज में लेते हुए केवल इतना कहा, "उन्हें शुभकामनाएं।" लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। प्रमिला जयपाल ने नैन्सी मेस के प्रस्ताव को नस्लवादी, संकीर्ण सोच वाला और प्रवासियों का अपमान करने वाला कदम बताया। जयपाल ने कहा कि जब अमेरिकी जनता महंगाई, किराया और रोजमर्रा की परेशानियों से जूझ रही है तब नैन्सी मेस जैसे नेता असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं।

लेकिन विवाद ने और विस्फोटक रूप तब लिया जब दक्षिण कैरोलाइना के गवर्नर पद के रिपब्लिकन प्राथमिक चुनाव में नैन्सी मेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में वह पांचवें स्थान पर रहीं। इसके बाद इल्हान उमर ने उन पर तीखा तंज कसते हुए कहा, "तुम जहां से आई हो वहां का एक तरफा टिकट तुम्हारे नाम पर तैयार है।" यह टिप्पणी सीधे तौर पर उसी पुराने बयान की याद दिलाने वाली थी जब नैन्सी मेस ने इल्हान उमर से कहा था कि उनके नाम का एक तरफा टिकट सोमालिया के लिए तैयार है।

इल्हान उमर की इस टिप्पणी पर नैन्सी मेस ने बेहद आक्रामक अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने कहा, "तुम मेरे बारे में कुछ भी कह लो, लेकिन मैं कभी अपने भाई से शादी नहीं करूंगी।" यह बयान इल्हान उमर को लेकर लंबे समय से चल रहे उन विवादों की ओर इशारा माना गया जिनमें उन पर अपने भाई से विवाह करने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। हालांकि उमर इन आरोपों को पहले भी नकार चुकी हैं, लेकिन अमेरिकी राजनीति में यह मुद्दा बार-बार उछलता रहा है। एक अमेरिकी सांसद ने टीवी चैनल से बातचीत करते हुए आरोप लगाया है कि इल्हान उमर ने अपने भाई अहमद नूर सईद एल्मी से शादी की थी ताकि उन्हें अमेरिका में रहने और पढ़ाई करने के लिए कानूनी दस्तावेज मिल सकें। उन्होंने कहा कि बाद में जब यह मामला सार्वजनिक हुआ, तो 2017 में दोनों का तलाक हो गया और इसके बाद इल्हान उमर ने अहमद अब्दिसलान हिरसी से विवाह किया। उन्होंने यह भी कहा कि 2019 में इल्हान उमर के निजी जीवन को लेकर फिर विवाद खड़ा हुआ, जब उनके राजनीतिक सलाहकार टिम माइनट के साथ अनैतिक संबंधों की खबरें सामने आईं। साथ ही यह भी आरोप लगाए गए कि 2018 से 2020 के बीच उनकी चुनावी कैंपेन से माइनट की कंपनी को बड़ी रकम का भुगतान किया गया। इन घटनाओं के चलते इल्हान उमर लगातार राजनीतिक और व्यक्तिगत विवादों के केंद्र में बनी रहीं।

इसके अलावा, कई राजनीतिक विश्लेषकों और सामाजिक संगठनों ने माना है कि इल्हान उमर पर किया गया कटाक्ष केवल व्यक्तिगत हमला नहीं था, बल्कि यह उनके धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की ओर भी इशारा करता दिखाई दिया। इल्हान उमर मुस्लिम समुदाय से आती हैं जहां रिश्तों की परवाह किये बिना शादी करने की खबरें आम रहती हैं। आलोचकों का कहना है कि नैन्सी मेस का बयान राजनीतिक जवाब से आगे बढ़कर पहचान और धर्म आधारित हमले जैसा नजर आया, जिसने अमेरिका में पहले से चल रही धार्मिक और सामाजिक ध्रुवीकरण की बहस को और तेज कर दिया।

उधर, इस विवाद में एक और सांसद सारा मैकब्राइड भी कूद पड़ीं। उन्होंने नैन्सी मेस की चुनावी हार पर तंज कसते हुए व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। इसके जवाब में नैन्सी मेस ने एक और तीखा बयान जारी करते हुए कहा कि कम से कम उन्हें अपने लिंग को लेकर कभी भ्रम नहीं रहा और न ही वह अपने भाई से शादी करेंगी।

अभियान

जहां रहस्य से मिलती है साधना: कसार देवी की अनकही कहानी

हिमालय की शांत वादियों में कुछ स्थान ऐसे हैं जो केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और रहस्यमयी महत्व के कारण भी विशेष पहचान रखते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित कसार देवी मंदिर ऐसा ही एक स्थान है, जिसने वर्षों से श्रद्धालुओं, साधकों, पर्यटकों और शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह मंदिर केवल पूजा-अर्चना का केंद्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थल माना जाता है जहां प्रकृति, अध्यात्म और रहस्य एक साथ मिलकर एक अद्भुत अनुभव का निर्माण करते हैं। जो भी व्यक्ति यहां पहुंचता है, वह केवल मंदिर के दर्शन ही नहीं करता, बल्कि एक ऐसी अनुभूति लेकर लौटता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना आसान नहीं होता।

उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और इसके पीछे कारण भी स्पष्ट है। यहां के पर्वत, नदियां, जंगल और प्राचीन मंदिर सदियों से ऋषियों, मुनियों और साधकों की तपस्थली रहे हैं। इन्हीं तपस्थलों में कसार देवी मंदिर का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। अल्मोड़ा नगर से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। यहां पहुंचते ही वातावरण में एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होता है। चारों ओर फैली हरियाली, दूर दिखाई देती हिमालय की चोटियां, पक्षियों का मधुर कलरव और शुद्ध पर्वतीय हवा मन को तुरंत सुकून प्रदान करती है। ऐसा लगता है मानो समय की गति यहां कुछ क्षणों के लिए धीमी पड़ गई हो। कसार देवी मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन माना जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर लगभग दो हजार वर्ष पुराना है और यहां देवी शक्ति की उपासना सदियों से होती आ रही है। स्थानीय लोगों के बीच यह स्थान गहरी आस्था का केंद्र है। उनके अनुसार यहां मां कसार देवी की विशेष कृपा रहती है और जो भी श्रद्धा के साथ यहां आता है, उसे मानसिक संतोष और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। यही कारण है कि हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन कसार देवी मंदिर को केवल धार्मिक महत्व ने ही प्रसिद्ध नहीं बनाया। इसकी ख्याति का सबसे बड़ा कारण इससे जुड़ा रहस्य है। वर्षों से यह कहा जाता रहा है कि मंदिर के आसपास का क्षेत्र विशेष प्रकार की चुंबकीय और भू-ऊर्जात्मक शक्तियों से प्रभावित है। अनेक लोग दावा करते हैं कि यहां ध्यान करने पर मन अत्यंत शीघ्र शांत हो जाता है और एकाग्रता का स्तर सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव मानते हैं, जबकि कुछ इसे प्राकृतिक भू-चुंबकीय गतिविधियों से जोड़ते हैं। यही कारण है कि यह स्थान केवल श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए भी आकर्षण का विषय बना रहा है।

लोकप्रिय मान्यताओं के अनुसार कसार देवी क्षेत्र पृथ्वी के उन दुर्लभ स्थलों में से एक है जहां विशेष भू-चुंबकीय प्रभाव महसूस किए जाते हैं। कई लेखों और चर्चाओं में इसका संबंध वैन एलेन बेल्ट से जोड़ा जाता है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से वैन एलेन बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में मौजूद विकिरण क्षेत्रों को कहा जाता है, फिर भी कसार देवी के संदर्भ में यह शब्द रहस्यमयी ऊर्जा क्षेत्र के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। यही वजह है कि इस मंदिर के बारे में अनेक कहानियां और चर्चाएं समय-समय पर सामने आती रही हैं। लोग इसे विज्ञान और अध्यात्म के संगम के रूप में देखने लगे हैं।

कहा जाता है कि यहां आने वाले अनेक साधकों ने ध्यान के दौरान असाधारण शांति और आत्मिक अनुभव प्राप्त किए हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और मानसिक तनाव से परेशान लोग जब यहां कुछ समय बिताते हैं, तो उन्हें एक अलग प्रकार का सुकून महसूस होता है। यह अनुभव केवल किसी धार्मिक भावना तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति की गोद में मिलने वाली गहरी मानसिक शांति का भी परिणाम हो सकता है। पहाड़ों की नीरवता, स्वच्छ वातावरण और प्राकृतिक ऊर्जा मनुष्य के मन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, जिसे यहां आने वाले लोग सहज रूप से महसूस करते हैं। कसार देवी मंदिर की प्रसिद्धि में स्वामी विवेकानंद का नाम भी विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में स्वामी विवेकानंद इस क्षेत्र में आए थे और कुछ समय तक यहां ध्यान एवं साधना की थी। कहा जाता है कि इस स्थान की आध्यात्मिक शक्ति और प्राकृतिक वातावरण ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया था। उन्होंने यहां बिताए समय को अपने जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों में शामिल किया। विवेकानंद जैसे महान विचारक का इस स्थान से जुड़ना कसार देवी की आध्यात्मिक प्रतिष्ठा को और अधिक मजबूत बनाता है।

समय के साथ यह स्थान केवल भारतीय साधकों तक सीमित नहीं रहा। बीसवीं शताब्दी के मध्य में जब पश्चिमी देशों में आध्यात्मिकता और भारतीय दर्शन के प्रति रुचि बढ़ी, तब अनेक विदेशी यात्री यहां पहुंचने लगे। विशेष रूप से 1960 और 1970 के दशक में यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गया। उस समय दुनिया भर से लोग शांति, ध्यान और आत्मिक खोज के लिए भारत आ रहे थे। अल्मोड़ा की पहाड़ियों में स्थित कसार देवी उनके लिए एक आदर्श स्थान बन गया। धीरे-धीरे यहां विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा बढ़ने लगा और यह क्षेत्र "हिप्पी हिल" के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया।

विश्व प्रसिद्ध संगीतकार जॉर्ज हैरिसन, कवि एलन गिन्सबर्ग, गायक बॉब डायलन और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय हस्तियां इस क्षेत्र में आ चुकी हैं। इन लोगों ने यहां के वातावरण और आध्यात्मिक अनुभूति की खुलकर सराहना की। उनके अनुभवों और यात्राओं ने कसार देवी को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी यूरोप, अमेरिका, जापान और अन्य देशों से बड़ी संख्या में लोग यहां ध्यान और योग के लिए आते हैं।

कसार देवी मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यहां का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। कुछ लोग यहां देवी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आते हैं, कुछ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने पहुंचते हैं, जबकि कुछ आत्मिक खोज और मानसिक शांति की तलाश में यहां आते हैं। लेकिन लगभग सभी लोग इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि यहां का वातावरण अत्यंत शांत और सकारात्मक है। पहाड़ों की नीरवता और प्रकृति की विशालता मनुष्य को स्वयं के भीतर झांकने का अवसर देती है।

मंदिर के आसपास का क्षेत्र भी पर्यटन की दृष्टि से बेहद आकर्षक है। निकट स्थित बिनसर वन्यजीव अभयारण्य प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अद्भुत स्थान है। यहां अनेक प्रकार के पक्षी, वन्यजीव और दुर्लभ वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का दृश्य इतना मनमोहक होता है कि पर्यटक घंटों तक प्रकृति के इस सौंदर्य को निहारते रहते हैं। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती सूर्य की सुनहरी किरणें पूरे वातावरण को अलौकिक बना देती हैं।

स्थानीय संस्कृति में भी कसार देवी मंदिर का विशेष स्थान है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहां भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं और देवी की आराधना करते हैं। यह आयोजन केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि स्थानीय परंपराओं, लोक संस्कृति और सामाजिक एकता का भी महत्वपूर्ण उत्सव है। मेले के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण से भर जाता है और दूर-दूर से आए लोग यहां की सांस्कृतिक झलक का आनंद लेते हैं। आज के आधुनिक युग में जब मनुष्य तकनीक और भौतिक उपलब्धियों के पीछे लगातार दौड़ रहा है, तब कसार देवी जैसे स्थान हमें जीवन के दूसरे पहलू की याद दिलाते हैं। यह स्थान बताता है कि मानसिक शांति, आत्मिक संतुलन और प्रकृति के साथ जुड़ाव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी भौतिक सफलताएं। शायद यही कारण है कि यहां आने वाले लोग केवल पर्यटक बनकर नहीं लौटते, बल्कि अपने भीतर कुछ नया अनुभव करके वापस जाते हैं।

कसार देवी मंदिर आज भी रहस्य, आस्था और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रतीक बना हुआ है। चाहे कोई इसे धार्मिक दृष्टि से देखे, प्राकृतिक ऊर्जा का केंद्र माने या फिर ध्यान और आत्मचिंतन की सर्वोत्तम जगह समझे, यह स्थान हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में प्रभावित अवश्य करता है। हिमालय की गोद में बसा यह प्राचीन मंदिर हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के कुछ रहस्य अभी भी पूरी तरह समझे नहीं जा सके हैं और शायद यही अनजाना आकर्षण इसे इतना विशेष बनाता है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

प्रधानमंत्री के तौर पर श्री नरेन्द्र मोदी के 12 वर्ष : गुजरात एक मजबूत और सर्वसमावेशी स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ देशभर में अव्वल

▸▸ गुजरात में आज 19,000 से अधिक डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स कार्यरत, लगातार पांच वर्षों से केंद्र सरकार की स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में 'बेस्ट परफॉर्मर स्टेट'

▸▸ स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी के तहत 13,047 से अधिक स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स को पीओसी के स्तर पर सहायता, 4000 से अधिक आईपीआर फाइल किए गए

▸▸ 'आई-हब' द्वारा लगभग 750 स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन, इनक्यूबेशन और वित्तीय सहायता, इन स्टार्टअप्स द्वारा 4000 से अधिक रोजगार का सृजन

▸▸ महिला उद्यमियों के लिए 'वीस्टार्ट' पहल के अंतर्गत 269 महिला-संचालित स्टार्टअप्स को सहायता

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि यदि युवाओं के आइडियाज को उचित प्लेटफॉर्म, नीतिगत सहयोग और संसाधन मिलें, तो वे राष्ट्रनिर्माण के सबसे बड़े भागीदार बन सकते हैं। इसी सोच के साथ, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'स्टार्टअप इंडिया' पहल शुरू की गई, जिससे लाखों युवाओं को 'जॉब सीकर' से 'जॉब क्रिएटर' बनने की प्रेरणा मिली है।

उल्लेखनीय है कि 26 मई, 2026 को श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कर्यकाल के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन 12 वर्षों के दौरान देश में उद्यमशीलता की एक नई संस्कृति का निर्माण हुआ है, और भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम मबजूत हुआ है। उनके नेतृत्व में गत 12 वर्षों के दौरान गुजरात ने भी स्टार्टअप और इनोवेशन यानी नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात औद्योगिक विकास का केंद्र होने के साथ ही देश के एक अग्रणी स्टार्टअप हब के रूप में उभरा है।

भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) से मान्यता प्राप्त 19,000 से अधिक स्टार्टअप्स के साथ गुजरात आज देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। डीपीआईआईटी की स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात लगातार पांच वर्षों से 'बेस्ट परफॉर्मर स्टेट' बना हुआ है, जो दिखाता है कि सहायक नीतियों और नियोजित पहलों के जरिए राज्य में एक मजबूत और सर्वसमावेशी स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित किया गया है।

स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी के तहत 13,047 से अधिक स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के स्तर पर सहायता

राज्य के युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा स्टार्टअप और इनोवेशन के माध्यम से युवाओं की सृजनात्मक क्षमताओं को विकसित करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने 2017-18 से पांच वर्षों के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी (एसएसआईपी) घोषित की थी। इस पॉलिसी को मिली अभूतपूर्व सफलता के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में वर्ष 2022 में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 (एसएसआईपी 2.0) लॉन्च की गई। इस पॉलिसी के अंतर्गत नए क्षेत्रों के साथ-साथ परंपरागत और नए युग की टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि एसएसआईपी 1.0 और 2.0 के तहत अब तक कुल 13,047 से अधिक स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) के स्तर पर सहायता दी गई है, जबकि 4043 से अधिक बौद्धिक संपदा अधिकार (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट-आईपीआर) फाइल किए गए हैं। एसएसआईपी के तहत कुल 3287 से अधिक स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन और इनक्यूबेशन सहायता दी गई है। स्टार्टअप्स और इनोवेशन को आर्थिक सहायता देने के लिए एसएसआईपी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थाओं द्वारा 36.43 करोड़ रुपए के एसएसआईपी फंड का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, एसएसआईपी 1.0 और 2.0 के अंतर्गत पॉलिसी लागू होने के बाद से अब तक जागरूकता अभियान के माध्यम से 22.72 लाख से अधिक छात्रों को स्टार्टअप्स के विषय में मार्गदर्शन प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया है।

इतना ही नहीं, एसएसआईपी 2.0 पोर्टल पर अब तक स्कूली छात्रों के 1948 से अधिक स्टार्टअप प्रस्ताव रजिस्टर हुए हैं, जिनमें से लगभग 1141 छात्रों के स्टार्टअप प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। एसएसआईपी आज स्कूल स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक के छात्रों को मार्गदर्शन, मेंटरशिप, वित्तीय सहायता और बाजार तक पहुंच जैसी सर्वग्राही सुविधाएं प्रदान कर गुजरात में इनोवेशन संस्कृति को मजबूत बना रही है।

'आई-हब' : गुजरात के स्टार्टअप इकोसिस्टम का प्रमुख केंद्र, करीब 750 स्टार्टअप्स को सीधी सहायता

स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी (एसएसआईपी) के अंतर्गत गठित गुजरात स्टार्टअप एंड इनोवेशन हब (आई-हब) आज राज्य के इनोवेशन इकोसिस्टम का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। आई-हब राज्य में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कार्यरत सबसे बड़ी सुविधा है, जहां सिंगल विंडो सपोर्ट सिस्टम के जरिए कानूनी, वित्तीय और तकनीकी समेत योजना संबंधी मार्गदर्शन दिया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से जुड़ा केंद्रीकृत हब स्थापित करके, आई-हब स्टार्टअप्स को प्री-इनक्यूबेशन, इनक्यूबेशन और एक्सलरेशन के चरणों के दौरान उनके आइडियाज, उत्पादन और निवेश की जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करता है।

'आई-हब' की स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी, और अब तक इसके अंतर्गत लगभग 750 स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, इनक्यूबेशन सपोर्ट और वित्तीय सहायता दी गई है। स्टार्टअप सृजन सीड सपोर्ट योजना के तहत 400 से अधिक स्टार्टअप्स को 28 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। आई-हब के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स द्वारा राज्य में लगभग 4000 से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है। वहीं, इन स्टार्टअप्स का कुल बाजार मूल्य करीब 3569 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

आई-हब के जरिए स्टार्टअप्स को विभिन्न वेंचर फंड्स की ओर से 446 करोड़ रुपए से अधिक का निजी फंड उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही, आई-हब ने 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल के जरिए 20 से अधिक जिलों में अपनी पहुंच का विस्तार किया है और 4.5 लाख से अधिक युवाओं को स्टार्टअप और इनोवेशन के विषय में जागरूक किया है।

'वीस्टार्ट' पहल के तहत 269 महिला संचालित स्टार्टअप्स को सहायता

'वीस्टार्ट', आई-हब द्वारा महिला उद्यमियों के लिए शुरू की गई एक विशेष पहल है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के आइडियाज को सफल व्यवसाय में परिवर्तित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। उल्लेखनीय है कि इस पहल के तहत 269 महिला संचालित स्टार्टअप्स को सहायता दी गई है, जो आई-हब की ओर से समर्थन प्राप्त कुल स्टार्टअप्स का लगभग 36 फीसदी है। इसके अतिरिक्त, महिला उद्यमियों को उनके स्टार्टअप के प्रारंभिक चरण के दौरान गति देने और संसाधनों तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल (जीयूएसईसी) की ओर से 'हरस्टार्ट' कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। 'हरस्टार्ट' एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसके चलते अधिक से अधिक महिला उद्यमी अपने आइडियाज को पंख दे रही हैं, और राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना योगदान दे रही हैं। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने गुजरात औद्योगिक नीति के तहत भी स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन योजना घोषित की थी, जिसके परिणामस्वरूप अनेक स्टार्टअप्स ने अपने व्यवसाय और उत्पादों का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया है। इस नीति के तहत सीड सपोर्ट ने 471 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की है।

विकसित भारत के अमृत काल में स्टार्टअप्स केवल आर्थिक विकास का साधन ही नहीं, बल्कि नवाचार, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता का एक मजबूत स्तंभ भी है। आज गुजरात का स्टार्टअप इकोसिस्टम राज्य की सशक्त औद्योगिक परंपरा, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, सक्रिय नीतियों और युवा प्रतिभा के समन्वय का एक शानदार उदाहरण बन गया है।

'विकसित पोरबंदर' की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम

पोरबंदर में वर्ल्ड क्लास फर्नीचर पार्क के विकास के लिए उद्योग जगत के साथ आयोजित होगी उच्च स्तरीय समिट

गांधीनगर, 12 जून : पोरबंदर को वैश्विक स्तर के फर्नीचर उत्पादन केन्द्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में आगामी 13 जून, 2026 को 'विकसित पोरबंदर फर्नीचर पार्क समिट' का आयोजन किया गया है। इस समिट के अंतर्गत पोरबंदर में प्रस्तावित मेगा फर्नीचर पार्क की स्थापना की संभावनाओं, उसके विकास के लिए मार्गदर्शन एवं भविष्य की रणनीतिक कवायद के विषय में उद्योग जगत के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी।

इस कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री एवं पोरबंदर के सांसद डॉ. मनसुख मांडविया और गुजरात सरकार के मंत्री एवं पोरबंदर के विधायक श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया की प्रेरक उपस्थिति में हितधारकों के साथ संवाद आयोजित होगा। पोरबंदर में औद्योगिक विकास तथा आने वाले समय में औद्योगिक रूपरेखा के विस्तार के लिए यह समिट एक महत्वपूर्ण मंच सिद्ध होगी।

देशभर के फर्चनीर उद्योग जगत के अग्रणी होंगे सहभागी

फर्नीचर उत्पादन तथा उससे सम्बद्ध क्षेत्रों के उद्योगपतियों, उद्योग संगठनों व व्यापारिक मंडलों के प्रतिनिधियों सहित राज्यभर से 50 से अधिक प्रतिनिधियों को इस समिट में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा; विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा प्रतिष्ठित ब्रांड्स के प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रहेगी; जिनमें अहमदाबाद स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग, IKEA, Dato Sanso, Hettich, Merino, Royal Touch Laminates, Medoc और Aemor सहित गुजरात टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन, गुजरात टिम्पर ऑक्शन एसोसिएशन, गुजरात ग्रीन इकोनॉमिक चैम्बर तथा पोरबंदर स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित रहने वाले हैं।

विभिन्न सरकारी विभागों की भागीदारी

फर्नीचर पार्क की संभावित स्थापना के लिए आवश्यक एकीकृत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार के उद्योग विभाग, बंदरगाह विभाग सहित स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयों के उच्चाधिकारी भी इस समिट में भाग लेंगे और आवश्यक रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय साधकर भावी कार्यवाही के लिए मार्गदर्शक चर्चा की जाएगी।

स्थल निरीक्षण तथा स्थानीय व्यवस्था

समिट में भाग लेने आने वाले देश-विदेश के प्रतिनिधि 14 जून, 2026 को पोरबंदर में फर्नीचर पार्क के लिए प्रस्तावित स्थलों का दौरा भी करेंगे। पोरबंदर के निकट स्थित भारवाडा में इस पार्क निरीक्षण द्वारा प्रोजेक्ट की संभावनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा और स्थानीय स्तर पर जिन ढाँचागत सुविधाओं का विकास किए जाने की जरूरत है, उस संबंध में अवलोकन किया जाएगा।

इस अवसर पर पोरबंदर के विशिष्ट आतिथ्य तथा सौराष्ट्र की कला-संस्कृति का परिचय कराने के लिए प्रशासन द्वारा प्रतिनिधियों के स्वागत एवं आवश्यक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने वाला है।

पोरबंदर के औद्योगिक भविष्य के लिए आशावादी पहल

'विकसित पोरबंदर फर्नीचर पार्क समिट' केवल एक बैठक नहीं, बल्कि पोरबंदर को नए औद्योगिक आयामों की ओर ले जाने वाली दृष्टिपूर्ण पहल है। आशा व्यक्त की जा रही है कि यह समिट फर्नीचर क्षेत्र में निवेश, रोजगार के नए अवसर, स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन इकोसिस्टम के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका सकती है।

दिनांक 13 व 14 जून, 2026 को आयोजित होने वाली यह समिट पोरबंदर के विकास के नए अध्याय के प्रारंभ समान बन सकती है, जहाँ स्थानीय संभावनाओं को वैश्विक अवसरों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

मौत से मुकाबला: सातवीं मंजिल पर फंसे युवक को पुलिस ने दिखाई जिंदगी की राह

सूरत। गुजरात के सूरत शहर में पुलिस की बहादुरी, तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता का एक ऐसा उदाहरण सामने आया है, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। सातवीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में खुद को बंद कर चुके और जहरीला पदार्थ खा चुके युवक की जान बचाने के लिए पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना जोखिम उठाया और समय रहते उसे सुरक्षित अस्पताल पहुंचाकर एक बड़ी अनहोनी टाल दी। इस साहसिक कार्रवाई की पूरे शहर में चर्चा हो रही है और स्थानीय लोग पुलिसकर्मियों की जमकर सराहना कर रहे हैं।

घटना सूरत के लसकाना क्षेत्र की है, जहां एक युवक ने कथित रूप से जहरीली दवा का सेवन कर लिया और उसके बाद अपने फ्लैट के अंदर खुद को बंद कर लिया। स्थिति की गंभीरता तब सामने आई जब इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंची। जानकारी मिलते ही लसकाना पुलिस की पीसीआर-81 टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया गया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी किरणभाई और कृपाल सिंह ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बिना किसी देरी के घटनास्थल की ओर रुख किया।

मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने पाया कि युवक सातवीं मंजिल पर स्थित अपने

फ्लैट में बंद था और उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी। दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण सामान्य तरीके से उसके पास पहुंचना संभव नहीं था। समय बीतने के साथ युवक की जान को खतरा बढ़ता जा रहा था। ऐसे में पुलिसकर्मियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि किसी भी तरह युवक तक पहुंचा जाए और उसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए।

स्थिति का आकलन करने के बाद पुलिसकर्मियों ने एक साहसिक योजना बनाई। उन्होंने पड़ोसी इमारत की बालकनी के रास्ते युवक तक पहुंचने का फैसला किया। यह फैसला जितना आसान सुनने में लगता है, वास्तव में उतना ही जोखिम भरा था। सातवीं मंजिल की ऊंचाई पर जरा सी चूक भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। लेकिन युवक की जान बचाने के संकल्प ने पुलिसकर्मियों को पीछे हटने का अवसर नहीं दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिसकर्मियों ने बिना अपनी सुरक्षा की चिंता किए पड़ोसी इमारत की बालकनी से होते हुए युवक के फ्लैट तक पहुंचने का जोखिम उठाया। ऊंचाई पर संतुलन बनाए रखते हुए उन्होंने बेहद सावधानी और सूझबूझ के साथ युवक तक पहुंच बनाई। वहां पहुंचने पर उन्होंने युवक को संभाला और सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। इस पूरी कार्रवाई के दौरान आसपास मौजूद लोगों की सांसें थमी हुई थीं, क्योंकि किसी भी क्षण स्थिति गंभीर रूप ले सकती थी।

युवक को बाहर निकालने के बाद पुलिस ने समय गंवाए बिना उसे पीसीआर वाहन के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने तत्काल उपचार शुरू किया। चिकित्सकों के अनुसार यदि उपचार में थोड़ी भी देरी होती तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। समय पर अस्पताल पहुंचाए जाने के कारण युवक को आवश्यक चिकित्सा सहायता मिल सकी और उसकी जान बच गई। इलाज के बाद जब युवक को होश आया तो उसके परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली और पुलिस का आभार व्यक्त किया।

इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पुलिस केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने का ही कार्य नहीं करती, बल्कि कई बार लोगों की जान बचाने के लिए अपने जीवन को भी जोखिम में डाल देती है। किरणभाई और कृपाल सिंह की बहादुरी ने यह दिखा दिया कि कर्तव्यनिष्ठा और मानवता का भाव किसी भी चुनौती से बड़ा होता है। दोनों पुलिसकर्मियों ने जिस साहस और जिम्मेदारी का परिचय दिया, वह समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है।

घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने पुलिस टीम की खुलकर प्रशंसा की। लोगों का कहना है कि यदि पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंचती और इतना साहसिक कदम नहीं उठाती, तो परिणाम बेहद दुखद हो सकते थे। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी पुलिसकर्मियों के कार्य की सराहना करते हुए उन्हें वास्तविक नायक बताया है। युवक के परिजनों ने भी भावुक होकर पुलिस का धन्यवाद किया। उनका कहना है कि पुलिसकर्मियों की तत्परता और साहस की वजह से उनके परिवार का एक सदस्य आज जीवित है। उन्होंने कहा कि ऐसे पुलिसकर्मी समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को मजबूत करते हैं।

यह घटना केवल एक बचाव अभियान नहीं थी, बल्कि मानव जीवन के प्रति समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल भी थी।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया: दुर्व्यवहार बंद करो, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाओ मत

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर आपत्तिजनक कार्टून पोस्ट करने के आरोप में एक कार्टूनिस्ट को दंडात्मक कार्रवाई से बचाया। हालांकि, न्यायालय ने सोशल मीडिया पर बढ़ती आपत्तिजनक सामग्री पर चिंता व्यक्त की और इसे रोकने के लिए न्यायिक आदेश जारी करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीवन रेखा का काम करती है। प्रगतिशील सोच वाले समाज की परिपक्वता का एक संकेत यह है कि वह किसी की राय पर विचार करता है और चाहे तो उसे नजरअंदाज भी कर सकता है। समस्या यह है कि कई बार अभिव्यक्ति को संदेह की नजर से देखा जाता है, इसलिए इसे सीमित करने, यानी इस पर लगाम लगाने के प्रयास किए जाते हैं।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की चिंता जायज़ हो सकती है, क्योंकि कुछ समय से सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने या प्रसारित करने की होड़ लगी हुई है। हाल ही में, कुछ महीने पहले, एक यूट्यूब चैनल पर एक कार्यक्रम के दौरान आपत्तिजनक भाषा, महिला विरोधी टिप्पणियां और विकलांगों का मज़ाक उड़ाने वाली सामग्री प्रसारित की गई, जिसे स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति के अधिकार का दुरुपयोग माना गया। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन तय करेगा और किस आधार पर तय किया जाएगा कि वह अभिव्यक्ति आपत्तिजनक है या नहीं? और फिर भी, अगर अभिव्यक्ति को सीमित करने वाले नियमों और उसके स्वरूप का दुरुपयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा?

इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सरकार को अपने फायदे के लिए सच्चाई और तथ्यों को तौलना शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अभिव्यक्ति के अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। यह भी उतना ही सच है कि हमारी सरकारों का नशा बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए सरकार अपनी ही आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी वजह से सरकार अपने आलोचकों को कई तरह से परेशान करती है। इसके कई उदाहरण पहले भी दर्ज किए जा चुके हैं। अंततः, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकना भी जरूरी है, क्योंकि देश में लोकतंत्र है, इसलिए इस स्वतंत्रता का गला घोंटना भी जरूरी है।

नासिरनगर विध्वंस विवाद: एसएमसी-एसओजी के विरोधाभासी बयानों के बीच लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत के वेड दरवाजा के पास नासिर नगर में लगभग 150 मिट्टी की ईंटों से बने मकानों को गुपचुप तरीके से गिराए जाने से एसएमसी और एसओजी (नगर निगम) की नींद उड़ गई है। इस विध्वंस मामले में, जिसमें नगर निगम की टीम अब तक कहती आ रही थी कि विध्वंस कार्य में उनकी कोई भूमिका नहीं है, बारह साल और बारह दिन बाद जोनल प्रमुख आशीष नायक ने एक वीडियो जारी कर कहा कि सूरत नगर निगम द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से कानूनी बताया जा रहा है। वहीं, सूरत नगर निगम के उपायुक्त एम. नागरजन ने 11/06/2026 की शाम पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि विध्वंस किसने किया, यह जांच का विषय है। आयुक्त नागरजन ने कहा कि विध्वंस, पुलिस व्यवस्था और अन्य सवालों के जवाब में यह जांच की जा रही है। विभाग के उन उच्च अधिकारियों के खिलाफ क्या जांच होनी चाहिए जिनके खिलाफ शिकायत है? ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इस पूरी घटना में किसी भी तरह की अवैध तोड़फोड़ नहीं हुई थी, तो तोड़फोड़ के समय इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? और उन्होंने बारह दिनों तक शुतुरमुर्ग की तरह अपना चेहरा क्यों छिपाया और मीडियाकर्मियों से क्यों भागते रहे?

तो यहाँ मुख्य बात यह है कि एसएमसी और एसओजी पर लगे आरोपों के चलते, जोनल चीफ, जिन्हें ऊपर से इशारों-इशारों में जानकारी दी गई थी, को यह बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ा कि तोड़फोड़ नगर निगम द्वारा की गई थी। ऐसे में केंद्रीय जोन का कौन सा अधिकारी सच बोल रहा है और कौन अपराधियों को बचा रहा है? इस पर भी संदेह पैदा हो रहा है। साथ ही, मीडिया पर भी पूरी तोड़फोड़ की घटना को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लग रहा है।

दरअसल, नासिर नगर के पास स्थित निजी परियोजना के लाभ के लिए, नियमों और नीतियों की अनदेखी करते हुए, बिल्डर के हित में नगरपालिका अधिकारियों द्वारा तोड़फोड़ का काम किए जाने के आरोपों के बाद भारी हंगामा हुआ। नगर निगम का कहना है कि उनकी टीम सड़क का सीमांकन और उसे खोलने के लिए पहुंची थी। यह काम नगरपालिका के नियमों और नीतियों के तहत किया गया था और नगर निगम ने इस संबंध में जो कहा, उससे वह हैरान है। जब मीडिया स्पष्टीकरण के लिए नगर आयुक्त एम. नागराजन से पूछने गया, तो मीडिया के कैमरे देखकर नगर आयुक्त और इंजीनियर आशीष नायक भाग गए और सम्मेलन कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया गया। जब मीडिया ने हॉल में प्रवेश करने की कोशिश की, तो मार्शल और पुलिस ने मीडिया को रोककर लाठियों से पीटा। यह स्पष्ट है कि लोकतंत्र का दमन किया जा रहा है।

एक साल बाद भी अनसुलझे सवाल: अहमदाबाद विमान हादसे की जांच कहां तक पहुंची, क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ और इकलौते जीवित बचे यात्री?

नई दिल्ली। देश के सबसे दर्दनाक विमान हादसों में गिने जाने वाले अहमदाबाद विमान दुर्घटना को एक वर्ष पूरा हो चुका है, लेकिन इस हादसे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न अब भी अनुत्तरित हैं। पिछले वर्ष 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। विमान में सवार 242 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से 241 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जमीन पर भी कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। कुल मिलाकर इस भीषण हादसे में 260 लोगों की मृत्यु हुई थी। यह दुर्घटना केवल एक विमान हादसा नहीं थी, बल्कि सैकड़ों परिवारों के सपनों, उम्मीदों और जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देने वाली त्रासदी बन गई।

हादसे के एक वर्ष बाद भी इसकी जांच जारी है और देश-विदेश की विमानन एजेंसियां दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी हुई हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हाल ही में जानकारी दी कि जांच प्रक्रिया पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और पेशेवर मानकों के तहत आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विमानन नियमों का पालन करते हुए विशेषज्ञों की टीम हर पहलू का गहन अध्ययन कर रही है। दुर्घटना के पीछे तकनीकी खराबी, मानवीय त्रुटि, मौसम संबंधी परिस्थितियां या अन्य संभावित कारणों की बारीकी से जांच की जा रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल दुर्घटना के कारणों की पहचान करना नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा सुधारों को लागू करना भी है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट पूरी होने के बाद उसके निष्कर्षों के आधार पर विमानन सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सरकार और विमानन क्षेत्र से जुड़े सभी संस्थान इस मामले को अत्यंत संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ देख रहे हैं। दुर्घटना की जांच भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) द्वारा की जा रही है। जांच एजेंसियों ने विमान के ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर और अन्य तकनीकी उपकरणों से प्राप्त आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण किया है। इसके अतिरिक्त विमान के रखरखाव रिकॉर्ड, उड़ान संचालन संबंधी दस्तावेज, मौसम संबंधी रिपोर्ट और चालक दल के प्रशिक्षण रिकॉर्ड की भी समीक्षा की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बड़े विमान हादसे की जांच एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि प्रत्येक तथ्य और तकनीकी संकेत की पुष्टि करना आवश्यक होता है।

इस मामले में विमान निर्माता कंपनी बोइंग भी जांच में सहयोग कर रही है। हादसे की पहली बरसी पर कंपनी ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। अपने आधिकारिक बयान में बोइंग ने कहा कि वह जांच एजेंसियों को हर संभव तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में पूर्ण सहयोग देगी। कंपनी ने यह भी दोहराया कि विमानन सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और वह जांच प्रक्रिया के निष्कर्षों का सम्मान करेगी।

हादसे का वह दिन आज भी लोगों की स्मृतियों में ताजा है। विमान ने उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद नियंत्रण खो दिया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान तेजी से नीचे आया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विस्फोट और आग की लपटों ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। बचाव दल, दमकलकर्मी और स्थानीय प्रशासन तत्काल मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी थी। दुर्घटनास्थल पर चारों ओर मलबा, धुआं और तबाही का भयावह दृश्य दिखाई दे रहा था। इस भीषण त्रासदी के बीच एक नाम ऐसा था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा—विश्वास कुमार रमेश। विमान में सवार यात्रियों में वे अकेले व्यक्ति थे जो जीवित बच पाए। शुरुआत में जब उनके जीवित होने की खबर सामने आई तो लोगों को इस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। अनेक लोगों ने इसे चमत्कार बताया। लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हुआ कि जीवन बच जाना कहानी का अंत नहीं था, बल्कि उनके संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू हुआ था।

पश्चिम रेलवे द्वारा साबरमती ⇌ सुल्तानपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी

ट्रेन क्र.	प्रस्थान स्टेशन और गंतव्य	चलाने के दिन	प्रस्थान	आगमन
04215	साबरमती - सुल्तानपुर (साप्ताहिक)	18.05.2026 से 13.07.2026	08:50 (सोमवार)	17:00 (दूसरे दिन)
04216	सुल्तानपुर - साबरमती (साप्ताहिक)	17.05.2026 से 12.07.2026	04:00 (रविवार)	07:20 (दूसरे दिन)

होल्ट: मेहसाणा, पालनपुर जंक्शन, आबू रोड, पिंडवाड़ा, सुमेरपुर मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर जंक्शन, किशनगढ़, जयपुर जंक्शन, बांदीकुई जंक्शन, भरतपुर जंक्शन, आगरा कैंट, इटावा जंक्शन, कानपुर सेंट्रल जंक्शन, लखनऊ जंक्शन, जवाई बांध, फालना, रानी दोनों दिशाओं में ।

कोच: AC 3-टियर इकोनॉमी और जनरल सेकंड क्लास कोच।

ठहराव के समय और ट्रेन की बनावट के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएं।

ट्रेन नंबर 04215 के लिए बुकिंग दि.09.05.2026 से सभी PRS काउंटरों और IRCTC वेबसाइट पर शुरू होगी। यह ट्रेन स्पेशल किराए पर स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
facebook.com/WesternRly
X.com/WesternRly
Instagram.com/WesternRly
https://www.youtube.com/@WesternRly
https://bit.ly/WesternRailwayOfficial
हमें लाईक और फोलो करें

कृपया सभी आरक्षित टिकटों के लिए मूल पहचान पत्र साथ रखें

बारह वर्ष जनविश्वास के, विकास के, जनकल्याण के

गुजरात के गांवों में विकास की गति तेज

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 6 लाख से अधिक परिवारों को मिले घर
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 4,557 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार का सृजन
- गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन लिमिटेड के प्रयासों से 26 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं का हुआ आर्थिक सशक्तीकरण
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वॉटरशेड कंपोनेंट) के तहत 617 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 1.36 लाख से अधिक कार्य पूर्ण
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 44 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण

गांधीनगर : गुजरात ने पिछले 12 वर्षों में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 12 वर्षों के नेतृत्व में गुजरात के गांवों का कायाकल्प हो रहा है। गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दूरदर्शी मार्गदर्शन और ग्रामीण विकास मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावळिया के नेतृत्व में ग्रामीण विकास विभाग ने प्रगति के नए शिखर हासिल किए हैं। राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), पीएम - जनमन, वॉटरशेड डेवलपमेंट तथा गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन लिमिटेड (जीएलपीसी) की अनेक कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की जा रही है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना : रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा के लिए आशीर्वाद के रुप में साबित हुई है। इस योजना के माध्यम से पिछले 12 वर्षों में राज्य में कुल 4,557 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है। योजनांतर्गत जल संरक्षण, कृषि भूमि विकास, वृक्षारोपण तथा पशुपालन आधारित 19 लाख से अधिक श्रम केंद्रित कार्य किए गए हैं।

केंद्र और राज्य सरकार के डिजिटल गवर्नेंस विजन के तहत मनरेगा में पारदर्शिता लाने के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) लागू किए गए हैं। इसके अलावा नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप, ड्रोन निरीक्षण, जियोटैगिंग और जियोफेंसिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी से कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है तथा कार्यों की पुनरावृत्ति भी रुकी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) : बेघर परिवारों को मिला आश्रय

ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को गौरवपूर्ण जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2016 से लागू प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक 8.29 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 30 अप्रैल 2026 तक 6.99 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 1.38 लाख से अधिक आवास निर्माणाधीन हैं। इस कार्य के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 9,213 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया गया है। केंद्र तथा राज्य सरकार के 60:40 के भागीदारी वाली इस योजना में लाभार्थी को नियमित रूप से 1.20 लाख रुपए की सहायता मिलती है। लेकिन मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के संवेदनशील दृष्टिकोण के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से 100 प्रतिशत राज्य अंश के तहत रूफ-कास्ट स्तर पर अतिरिक्त 50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है, जिससे कुल सहायता राशि 1.70 लाख रुपए हो गई है। इसके अलावा मनरेगा योजना के तहत 90 दिनों की मजदूरी के रूप में 25,920 रुपए तथा शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपए की सहायता भी प्रदान की जाती है। समय पर आवास पूरा करने वाले लाभार्थियों को 'मुख्यमंत्री प्रोत्साहक योजना' के तहत अतिरिक्त 20 हजार रुपए तथा महिलाओं के लिए बाथरूम निर्माण के लिए 5 हजार रुपए की सहायता दी जाती है।

पीएम - जनमन : आदिम जनजातीय समूहों के बेघर परिवारों को मिला आश्रय

वर्ष 2023 से शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम - जनमन) के अंतर्गत राज्य के अत्यंत पिछड़े आदिम जनजातीय समूहों (पीवीटीजीस) जैसे काठोडी, कोटवाळिया, पाढर, सिद्दी और कोलगा परिवारों के लिए 226 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 9,151 पक्के आवासों का निर्माण पूरा किया गया है। इस योजना में लाभार्थी को 2 लाख रुपए की सहायता सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) : ओडीएफ प्लस मॉडल की ओर अग्रसर गुजरात

ग्रामीण स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में गुजरात ने देशभर में अग्रणी स्थान बनाए रखा है। पिछले 12 वर्षों में इस मिशन के अंतर्गत 7,162.37 करोड़ रुपए के प्रावधान के मुकाबले 5,994.54 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 2 अक्टूबर 2019 को राष्ट्र को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किए जाने के बाद अब फेज-2 के तहत 'ओडीएफ प्लस मॉडल' गांवों के निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राज्य में अब तक 44.82 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर ठोस और तरल कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए 1.74 लाख सामुदायिक सोकपिट, 56,369 सामुदायिक कम्पोस्ट पिट तथा 13,575 सेग्रीगेशन शेड बनाए गए हैं। 'वेस्ट टू वेल्थ' दृष्टिकोण के तहत गोबरधन योजना के अंतर्गत 33 जिलों में 38 क्लस्टर आधारित बायोगैस प्लांट और 14,000 व्यक्तिगत बायोगैस प्लांट स्थापित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वॉटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट) के तहत पिछले 12 वर्षों में 617.90 करोड़ रुपए की लागत से 1,36,589 कार्य पूरे किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य परियोजना क्षेत्र में भूमि, जल, वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रबंधन कर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है। योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, भूमि सुधार तथा आजीविका विकास जैसी गतिविधियां संचालित की जाती हैं; जिससे ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। योजना अंतर्गत चैकडेम, तालाब, कॉजवे तथा खेत तालाब जैसे जल संचयन ढांचे बनाए जाते हैं, जिससे वर्षा का पानी बहकर न जाए और उसका संग्रहण हो सके। पानी के जमीन में रिसाव से भूजल स्तर में वृद्धि होती है तथा कुओं और बोरवेलों में पानी की उपलब्धता बढ़ती है।

जीएलपीसी : सखी मंडलों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण और 'लखपति दीदी' का संकल्प

गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड (जीएलपीसी) राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रभावी माध्यम बनी है। डे-एनआरएलएम के अंतर्गत राज्य के 248 तहसीलों में 26.25 लाख ग्रामीण महिलाओं को जोड़कर 2.82 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजीस) का गठन किया गया है। इन समूहों को रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड तथा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक लिंकेज उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के 'लखपति दीदी' अभियान के अंतर्गत गुजरात की 6 लाख से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं। सखी मंडलों की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय मेले, सरस मेले तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही 300 से अधिक केंद्रों पर संचालित 'मंगलम कैंटीन' महिलाओं को नियमित आय का स्रोत प्रदान कर रही हैं।

तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में राज्य की ऐतिहासिक पहल : गुजरात नॉलेज सोसाइटी (जीकेएस) तथा अमेरिका की वैश्विक अग्रणी कंपनी बेंटले सिस्टम्स के बीच रणनीतिक भागीदारी

- एमओयू से राज्य के सभी 16 सरकारी इंजीनियरिंग तथा 31 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के 14800 से अधिक विद्यार्थियों और 300 से अधिक अध्यापकों को मिलेगा आधुनिक टेक्नोलॉजी का निःशुल्क ज्ञान
- सरकार पर किसी भी प्रकार के वित्तीय बोझ के बिना विद्यार्थियों को डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, वॉटर नेटवर्क तथा डिजिटल ट्विन जैसे क्षेत्रों में प्रैक्टिकल प्रशिक्षण मिलेगा

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री त्रिकमभाई छांगा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गुजरात नॉलेज सोसाइटी (जीकेएस) और अमेरिका की वैश्विक अग्रणी कंपनी बेंटले सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच रणनीतिक भागीदारी का एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।

गुजरात सरकार के तकनीकी शिक्षा निदेशक कार्यालय अंतर्गत कार्यरत गुजरात नॉलेज सोसाइटी (जीकेएस) तथा अमेरिका की डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की वैश्विक अग्रणी कंपनी बेंटले सिस्टम्स के बीच एक महत्वपूर्ण अवाणिज्यक (नॉन-कॉमर्शियल) रणनीतिक भागीदारी के लिए एमओयू किया गया है। इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य राज्य के इंजीनियरिंग क्षेत्र के विद्यार्थियों को ग्लोबल इंडस्ट्री प्रैक्टिसेज से सज्ज कर रोजगारपरक बनाना है।

इस भागीदारी अंतर्गत राज्य के सभी 16 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा 31 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के लगभग 300 से अधिक अध्यापकों के लिए बेंटले के वैश्विक विशेषज्ञों द्वारा विशेष फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) का आयोजन किया जाएगा। इस अनूठी पहल का सीधा लाभ सिविल इंजीनियरिंग तथा उससे सम्बद्ध शाखाओं के लगभग 14800 से अधिक विद्यार्थियों को मिलेगा। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को माइक्रोस्टेशन, ओपनरोड्स, ओपनफ्लोस, सिंक्रो तथा डिजिटल ट्विन जैसे अत्याधुनिक डिजिटल इंजीनियरिंग टूल्स पर प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा; प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा, हेकाथॉन तथा डिजाइन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों में व्यावहारिक एवं तकनीकी कौशल का सुदृढ़ विकास किया जाएगा।

इस प्रस्तावित एमओयू अंतर्गत राज्य की तकनीकी शिक्षा को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को 65 से अधिक 'इंडस्ट्री-स्टैंडर्ड' बेंटले सॉफ्टवेयर निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त; विद्यार्थी घर बैठे या कॉलेज में अपनी अनुकूलता से सीख सकें; इसके लिए उन्हें 'बेंटले लर्न प्लेटफॉर्म' के माध्यम से सेल्फ-लर्निंग व अत्याधुनिक डिजिटल एजुकेशन की विशेष सुविधा दी जाएगी। इस पहल से विद्यार्थी केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रहते हुए वास्तविक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्रक्रिया और लाइव केस स्टडीज द्वारा सीधा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे।

यह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले विद्यार्थियों को गुजरात नॉलेज सोसाइटी तथा बेंटले सिस्टम्स द्वारा संयुक्त प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा, जो विद्यार्थियों के लिए वैश्विक स्तर के डिजिटल बेस तथा अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने का स्वर्ण अवसर समान बनेगा। इसी प्रकार; विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए उद्योग जगत के प्रमुख विशेषज्ञों के साथ सीधा संवाद, स्पेशल गेस्ट लैक्चर्स, इंटर्नशिप और इंडस्ट्रियल विजिट्स का भी व्यापक आयोजन किया जाएगा।

यह पहल केन्द्र सरकार के 'स्किल इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020' के विजन के साथ सुसंगत है। इस शैक्षणिक जुड़ाव के अंतर्गत राज्य के भावी इंजीनियर डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, अत्याधुनिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, स्मार्ट वॉटर नेटवर्क तथा डिजिटल ट्विन जैसी आगामी पीढ़ी की आधुनिक टेक्नोलॉजी में पूर्णतः निपुण एवं सक्षम बनेंगे।

इस भागीदारी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि राज्य सरकार पर किसी भी प्रकारके आर्थिक व वित्तीय बोझ के बिना तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जा सकेगा। इस ग्लोबल कनेक्ट से गुजरात के विद्यार्थी अधिक कुशल, उद्योग-सज्ज (इंडस्ट्री-रेडी) तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनेंगे, जिसके दीर्घकालीन परिणाम के रूप में राज्य के बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वय में गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और गुजरात कुशल मानवबल (स्किल्ड मैनपावर) हब बनेगा। इस प्रकार; आज के डिजिटल युग में राज्य के युवा इंजीनियरों को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए गुजरात सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय किया है।

अहमदाबाद के समग्र विकास एवं रेलवे अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं रेलवे अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक

स्टेशन पुनर्विकास, 'फाटक मुक्त गुजरात' तथा यात्री सुविधाओं के विस्तार पर हुई व्यापक चर्चा

अहमदाबाद के समग्र विकास, रेलवे अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 जून, 2026 को अहमदाबाद के माननीय महापौर श्री हितेश बारोट, अहमदाबाद पश्चिम के माननीय सांसद श्री दिनेश मकवाना, अहमदाबाद महानगरपालिका की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री कमलेश पटेल तथा दरियापुर के माननीय विधायक श्री कौशिक जैन ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में रेलवे एवं अहमदाबाद महानगरपालिका के मध्य बेहतर समन्वय के माध्यम से विभिन्न विकासात्मक एवं जनहितकारी विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक के दौरान रेलवे अवसंरचना के समग्र सुदृढ़ीकरण, स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं, लेवल क्रॉसिंग उन्मूलन तथा 'फाटक मुक्त भारत' के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) एवं रोड अंडर ब्रिज (RUB) के निर्माण, नई रेल लाइनों के विस्तार सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर गहन एवं सार्थक चर्चा की गई। क्षेत्र के तीव्र शहरी विकास एवं बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक, सुरक्षित एवं निर्बाध रेल संपर्क सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा बहु-एजेंसी समन्वय को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दिया गया।

बैठक में माननीय महापौर श्री हितेश बारोट ने आंबली रोड स्टेशन के आसपास स्थित रेलवे भूमि के समुचित विकास एवं उसके बेहतर उपयोग के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए तथा शहर के तीव्र विकास को देखते हुए इस क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन योजनाएँ तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। अहमदाबाद महानगरपालिका की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री कमलेश पटेल ने मणिनगर स्थित रेलवे लेवल क्रॉसिंग संख्या-308 पर प्रस्तावित रेलवे ओवर ब्रिज के संबंध में स्थानीय नागरिकों की अपेक्षाओं एवं सुझावों से अवगत कराते हुए रेलवे एवं अहमदाबाद महानगरपालिका के समन्वित प्रयासों से इस महत्वपूर्ण परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने पर जोर दिया। दरियापुर के माननीय विधायक श्री कौशिक जैन ने अहमदाबाद स्टेशन के आसपास उपलब्ध रेलवे भूमि के ऐसे विकास का सुझाव दिया, जिससे स्थानीय नागरिकों एवं व्यापारिक गतिविधियों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया।

अहमदाबाद पश्चिम के माननीय सांसद श्री दिनेश मकवाना ने अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न अधोसंरचनात्मक एवं जनसुविधा विषयों को बैठक में रखते हुए रेलवे परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ओम नगर फाटक पर रोड अंडर ब्रिज के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की सहायता के लिए कहा और शीघ्र पूरा करने के लिए कहा। मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने बैठक के दौरान असारवा स्टेशन के चमनपुरा साइड पर द्वितीय प्रवेश द्वार की स्थापना, चामुंडा ब्रिज से बेहतर संपर्क व्यवस्था विकसित करने तथा प्लेटफॉर्म के विस्तार की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में भविष्य में आवश्यक अधोसंरचनात्मक विकास के माध्यम से इसे देश के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किए जाने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

बैठक के दौरान मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने जानकारी दी कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा 100 लाइनों वाला कोचिंग डिपो वटवा में विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गोरा-घूमा रोड अंडर ब्रिज (RUB) को शीघ्र ही आम जनता को समर्पित किए जाने के संबंध में भी सकारात्मक चर्चा हुई।

भावनगर एवं राजकोट मंडल के माननीय सांसदो के साथ बैठक में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय ने भावनगर एवं राजकोट मंडल के अन्तर्गत आनेवाले संसदीय क्षेत्रों के माननीय सांसदो के साथ राजकोट में बैठक की। सर्वप्रथम महाप्रबंधक श्री पाण्डेय द्वारा उपस्थित सांसदो का स्वागत किया गया तथा उन्हे भावनगर व राजकोट मंडल में नवीनतम यात्री सुविधाओं व उपलब्धियों की जानकारी दी गई। बैठक के दौरान माननीय सांसदो द्वारा उनके क्षेत्र की रेल समस्याओं, परियोजनाओं, ट्रेनों के स्टापेज, नयी ट्रेन चलाने तथा ट्रेनों के विस्तार, ट्रेनों के फेरे बढाने और ढांचागत परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं बहुमूल्य सुझाव दिये गए।

भावनगर एवं राजकोट मंडल क्षेत्राधिकार के कुल 6 माननीय सांसदों ने इस बैठक में भाग लिया, जिनमें माननीय श्री परषोत्तमभाई रुपाला, श्रीमती पूनमबेन माडम, श्री रामभाई मोकरिया, श्री केसरीदेवसिंह झाला तथा श्री राजेशभाई चुड़ासमा, श्री भरतभाई सुतरिया शामिल रहे। पोरबंदर के माननीय सांसद तथा केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा मामले एवं खेल मंत्री, श्री डॉ. मनसुखभाई मांडविया के प्रतिनिधि तथा माननीय सांसद श्री चंदूभाई शिहोरा के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में भावनगर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा, राजकोट मंडल रेल प्रबंधक श्री गिरिराज कुमार मीना तथा पश्चिम रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन उप महाप्रबंधक (सामान्य) श्री उज्जवल देव ने किया।

बैठक के दौरान, महाप्रबंधक श्री पाण्डेय ने माननीय सांसदों को वर्तमान में चल रही विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में अवगत कराया और कहा कि पश्चिम रेलवे अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभिन्न यात्री सुविधाओं को प्रदान करने में हमेशा अग्रणी रही है। माननीय सांसदों ने भी अपनी मांगों को रखा और इन मंडलों में चल रही परियोजनाओं की सकारात्मक प्रगति के प्रति अपनी संतुष्टि व्यक्त की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से करजण में हिताची एनर्जी द्वारा लगभग 2,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्थापित होने वाली फैक्ट्री का शिलान्यास

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- इस प्रोजेक्ट से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और एमएसएमई क्षेत्र को वेग मिलेगा
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' और 'ऊर्जा आत्मनिर्भरता' के संकल्प को साकार करने में गुजरात अग्रसर
- हिताची और गुजरात का 60 वर्ष पुराना अटूट संबंध और अधिक सुदृढ हुआहिताची
- एनर्जी इंडिया के सीईओ श्री वेणु ने गुजरात के प्रगतिशील इकोसिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में राज्य की अग्रणी भूमिका की सराहना की

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा जिले के करजण में हिताची एनर्जी द्वारा लगभग 2,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश से स्थापित की जाने वाली नई पावर ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के पद पर सबसे लंबे और सफल कार्यकाल के लिए श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजनरी लीडरशिप में भारत आज विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है।

मुख्यमंत्री ने करजण स्थित नए लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मर प्लांट की स्थापना के लिए कंपनी को बधाई देते हुए कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' अभियान को और सुदृढ बनाएगी तथा देश के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि इस नए प्लांट द्वारा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और कौशल विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, इस परियोजना के कारण आसपास के क्षेत्र की एमएसएमई इकाइयों के लिए भी विकास के नए द्वार खुलेंगे।

मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुई 'वाइब्रंट गुजरात समिट' के परिणामस्वरुप आज गुजरात विश्वभर के उद्योगपतियों के लिए निवेश का पसंदीदा गंतव्य बन गया है। हिताची तथा गुजरात के बीच 60 वर्ष पुराना संबंध का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जापानी कंपनियों का गुजरात पर विश्वास लगातार बढ़ता गया है। गुजरात के मजबूत औद्योगिक वातावरण, पारदर्शी नीतियों और उत्कृष्ट कानून-व्यवस्था के कारण आज फॉर्च्यून-500 में शामिल विश्व की बड़ी कंपनियों के लिए गुजरात 'सेकंड होम' बन गया है। राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गुजरात को 'इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट' के रूप में स्थापित किया है। कच्छ के खावडा में विकसित हो रहा 37 गीगावॉट का रिन्यूएबल हाइब्रिड पार्क पूर्ण होने के बाद गुजरात देश की 'एनर्जी कैपिटल' बन जाएगा। ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नीतियों के द्वारा राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास साध रहा है।

आगामी दिनों में बढ़ रही ग्रीन एनर्जी की मांग को पूरा करने के लिए मजबूत ट्रांसमिशन सिस्टम आवश्यक है; जिसमें हिताची एनर्जी की यह नई सुविधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 'विकसित भारत @ 2047' के संकल्प को साकार करने में आत्मनिर्भर ऊर्जा अर्थव्यवस्था द्वारा गुजरात महत्वपूर्ण योगदान देगा।

हिताची एनर्जी इन्डिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक तथा सीईओ श्री वेणु ने भारत की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि, "यह नई फैसिलिटी एक 'डिजिटल-फर्स्ट' ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री होगी, जो हाई - एंड मैन्युफेक्चरिंग द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के एकीकरण को वेग देगा तथा भारत को ट्रांसफॉर्मर्स के वैश्विक लॉन्चपैड के रूप में स्थापित करेगी।"

श्री वेणु ने गुजरात के प्रगतिशील इकोसिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में राज्य की अग्रणी भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि यह परियोजना 'मेक इन इंडिया' अभियान के अंतर्गत उच्च कौशल आधारित रोजगार का सृजन करेगी तथा स्थानीय सप्लाई चेन को मजबूत बनाएगी। उन्होंने जोड़ा कि कहा कि कंपनी अगले 25 वर्षों तक भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के प्रति कटिबद्ध है तथा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना भी जारी रखेगी।

हिताची एनर्जी के ट्रांसफॉर्मर बिजनेस के ग्लोबल सीईओ श्री ब्रूनो मेलिस ने भारत के ऊर्जा भविष्य और अगले 25 वर्षों के सतत विकास को वेग देने के लिए कंपनी की मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में 75 वर्षों से अधिक की समृद्ध विरासत के साथ कंपनी वर्ष 2028 तक एक नई अत्याधुनिक फैक्ट्री शुरू करने का लक्ष्य रखती है। यह फैक्ट्री 'मेक इन इंडिया' अभियान को और मजबूत बनाएगी तथा टेक्नोलॉजी के स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान देगी। उन्होंने बल देते हुए कहा कि यह नई सुविधा केवल एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं होगा, बल्कि इंजीनियरिंग, इनोवेशन और प्रतिभाशाली लोगों के सहयोग से विकसित अत्याधुनिक सिस्टम होगी, जो भारत और विश्व की स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री के करकमलों से जमनाबाई जनरल अस्पताल के प्रतिनिधि को कंपनी के सीएसआर फंड से भेंट की गई एम्बुलेंस की प्रतीकात्मक चाबी सौंपी गई।

इस कार्यक्रम में वडोदरा के सांसद श्री हेमांगभाई जोशी, करजण के विधायक श्री अक्षयभाई पटेल, राज्य के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार दास, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।